

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया आरोप 'मोदी सरकार संप्रग के कानूनों को कर रही कमजोर'

मुंबई : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस की 'भारत जोड़े यात्रा' का आज यानी रविवार को महाराष्ट्र में आखिरी दिन है। यात्रा महाराष्ट्र चरण के अंतिम दिन बुलढाणा जिले से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र से यह पदयात्रा रविवार रात को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा के 74वें दिन साईराम एग्री सेंटर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह छह बजे बुलढाणा के भेंडवल से फिर से शुरू हुई। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के जलगांव-जामोद में आदिवासी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यहां उन्होंने केन्द्र की भाजपा सरकार पर आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) द्वारा बनाए गए कानूनों

को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी तो इन कानूनों को मजबूत किया जाएगा।

मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी देश के 'पहले मालिक' हैं और उन्हें अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वन

अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है।

राहुल गांधी ने बताया वनवासी का मतलब

राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों को 'वनवासी' कहते हैं, लेकिन 'आदिवासी' और 'वनवासी' शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं। वनवासी का मतलब है कि आप केवल जंगलों में रह सकते हैं, शहरों में नहीं, आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते हैं और हवाई



जहाज से यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आदिवासियों की जमीन छीनकर अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इन कानूनों को मजबूत करेंगे और आपके कल्याण के लिए नए कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा करती थीं कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं। अगर आप आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को नहीं समझेंगे तो देश को नहीं समझ पाएंगे। बताया जा रहा है कि सोमवार को 'भारत यात्रियों' के लिए विश्राम दिवस रहेगा। इस दिन राहुल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे।

तेजी से आकार ले रहे मेट्रो-3 के स्टेशन

2024 तक शुरू करने का लक्ष्य!



मुंबई : मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो का काम फास्ट ट्रेक पर शुरू है। बताया गया कि पैकेज 1 के तहत 95 प्रतिशत सिविल वर्क कंसीट होने के साथ कई भूमिगत स्टेशन तेजी से आकार ले रहे हैं।

अंडरग्राउंड मेट्रो-3 के स्टेशनों के निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) तकनीक से किया जा रहा है। इसके तहत सुरंग कार्य के साथ कट एंड कवर मेथोडोलॉजी अपनाई जा रही है। सबसे व्यस्त इलाके कालबादेवी इलाके में मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अत्यंत संकरे क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है। यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। कालबादेवी के अलावा कफपरड, विधानभवन, चर्चिगेट और हुतात्मा चौक स्टेशन का काफी काम हो चुका

है। एमएमआरसी के अनुसार सीज, सिद्धिविनायक और एमआयडीसी स्टेशनों पर शतप्रतिशत ट्रेक बिछाने का काम हो चुका है। मुंबई सेन्ट्रल, विधानभवन स्टेशनों का काम भी अंतिम चरण में है।

गौरतलब है कि राज्य में नई शिदि-फडणवीस सरकार आने के बाद मेट्रो-3 के काम में काफी तेजी आई है। एमएमआरसी की एम डी अश्विनी भिडे लगातार कार्य की समीक्षा कर रही हैं। टनेल सेक्शन में कफपरड से विधानभवन तक ट्रेक का काम पूरा हो चुका है। स्टेशनों को शेपिंग दी जा रही है। प्लेटफॉर्म, एंटी-एग्जिट एस्केलेटर आदि कई काम चल रहे हैं। एमएमआरसी की टीम लक्ष्य के अनुसार काम को गति देने में लगी हुई है।

उद्धव ठाकरे को झटका...!

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न पर रोक का आदेश गलत नहीं

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के उस आदेश में कोई 'प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं' है, जिसमें शिवसेना में 'विभाजन' के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। शनिवार को जारी आदेश में न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा कि आयोग ने उपचुनावों की घोषणा के मद्देनजर चुनाव चिह्न के आवंटन के संबंध में तत्कालिकता को देखते हुए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।



अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जिसने बार-बार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में समय लिया। अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता और निर्वाचन आयोग की आलोचना नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने 15 नवंबर को निर्वाचन आयोग (ईसी) के अंतरिम आदेश के खिलाफ ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया था, और कहा था कि विस्तृत आदेश

बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आयोग द्वारा चुनाव चिह्न के मामले में अपनाई गई कार्रवाई उसके अधिकार क्षेत्र के तहत थी। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के बीच विवादों के पुराने मामलों में भी आरक्षित चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश देने वाले ऐसे ही अंतरिम आदेश पूर्व में भी पारित किए गए हैं। "इस प्रकार वर्तमान मामले में कुछ भी असामान्य या असाधारण नहीं है।" कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया है। शिवसेना का विवाद अभी थमा नहीं है।

मनसे नेताओं ने कल्याण में राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

कल्याण : महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने जहां कोशयारी पर महाराष्ट्र को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। वहीं मनसे नेता सड़क पर उतर कर राज्यपाल का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल्याण के शिवाजी चौक पर मनसे के कल्याण शहर संगठक रूपेश भोईर के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के बयान का विरोध करते हुए वापस जाने का नारा लगाया। गौरतलब हो कि औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत



सिंह कोशयारी ने कहा था कि जब हम स्कूल में थे तो पूछा जाता था कि आपके आदर्श कौन हैं। कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे, कुछ जवाहर लाल नेहरू को और कुछ महात्मा गांधी को। जिसे जो अच्छा समझता था, उसी का नाम लेता था। लेकिन भोईर के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के बयान का विरोध करते हुए वापस जाने का नारा लगाया। गौरतलब हो कि औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत

एक नए युग की बात कर रहा हूं। यहां डॉ. बाबासाहब आंबेडकर से लेकर नितीन गडकरी तक आपको आदर्श के रूप में मिल जाएंगे। राज्यपाल के इसी बयान का विरोध किया जा रहा है और विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा जगह-जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में कल्याण पश्चिम स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मनसे शहर संघटक रूपेश भोईर की अगुवाई में मनसे ने विरोध प्रदर्शन किया राज्यपाल कोशयारी वापस जाओ के नारे लगाए।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

दबाव मंजूर नहीं

पूरी दुनिया में व्याप्त जलवायु संकट से उबरने के प्रयासों में विकसित देशों द्वारा अपनी जवाबदेही से बचने और विकासशील देशों पर दबाव बनाने की कोशिशों को भारत ने सिरे से खारिज किया है। भारत ने अतीत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनों से सबक सीखते हुए सीओपी-27 में मुखर अभिव्यक्ति दी है। भारत ने कहा है कि अमीर देशों का दबाव मंजूर नहीं

होगा। शर्म-अल-शेख में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन से बचने की लड़ाई में किसी एक ही ईंधन को जवाबदेह ठहरा कर उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। हमारी मान्यता रही है कि सभी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग पूर्णतः बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। दरअसल, विकासशील देशों की अपनी सीमाएं हैं और वे विकसित देशों की तरह पूंजी व ईंधन के वैकल्पिक साधन जुटाने में सक्षम नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर भारत बीते साल ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किये गये समझौते की गंभीरता का सम्मान करता है। जिसके प्रति भारत ने प्रतिबद्धता जाहिर की है क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा के दायरे को बढ़ाता है। लेकिन विडंबना यही है कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कवायद में लगे हैं। साथ ही वे जीवाश्म ईंधनों में सिर्फ कोयले को ही खलनायक के रूप में दशार्ण की कोशिश में हैं। भारत को इस लिये निशाने पर लेने का प्रयास किया गया कि हमारे बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता पचास फीसदी के लगभग है। यह विडंबना ही है कि सीओपी के पहले मसौदे में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के भारत के प्रस्ताव को विकसित देशों ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बावजूद कि भारतीय सुझावों की गंभीरता का अहसास करते हुए यूरोपीय संघ और दुनिया के अन्य विकासशील व गरीब देशों ने इसका समर्थन किया था। उम्मीद है कि देर-सवेर भारत की रचनात्मक पहल का सम्मान होगा।

विडंबना ही है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का संकट जैसी भयावह स्थितियां पैदा कर रहा है उसको देखते हुए दुनिया की बड़ी शक्तियां गंभीरता नहीं दिखा रही हैं। बल्कि वे अपनी जवाबदेही विकासशील व गरीब देशों के हिस्से में डालने का प्रयास कर रही हैं। यही वजह है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु संरक्षण के लिये निर्धारित फंड की व्यवस्था पर स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही बल दिया कि जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिये आवश्यक प्रायोगिकी गरीब मुल्कों को उपलब्ध करायी जाये। इसके अलावा जलवायु संरक्षण के लिये जीवाश्म ईंधन का त्याग करने वाले देशों की मदद के लिये धन हस्तांतरण में तेजी लाने का आग्रह भी धनी देशों से किया। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी देशों द्वारा की जाने वाली आर्थिक मदद को जलवायु ऋण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह, भारत की दलील इस तार्किक व सुस्थापित आधार पर टिकी है कि विकसित देशों ने विश्व की औद्योगिक व्यवस्था का पहले और बड़ी मात्रा में दोहन किया है। जिसके लिये बड़े पैमाने पर अंधाधुंध जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया गया है। इसीलिए विकसित दुनिया ग्लोबल वार्मिंग तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं के लिये प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। जिसके चलते ही उन विकासशील देशों के लिये विकसित देशों को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, जो अभी भी अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल, भारत ने पेरिस समझौते की भावना का सहारा लेते हुए इस दलील की पैरवी की है कि विकासशील देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों की जरूरतों के हिसाब से ही आगे फैसले लेंगे।

✉ editor@rokhoklehaninews.com

🐦 Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

14 साल की स्टूडेंट से प्यार का नाटक कर टीचर ने कई बार किया रेप प्रेगनेंट होने पर उतारा मौत के घाट

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में गुरु और शिष्य का रिश्ता तार-तार हो गया। जैतपुर थाना इलाके में एक टीचर ने अपनी नाबालिग छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ कई बार रेप किया। रेप के बाद जब वह गर्भवती हो गई, तो आरोपी टीचर ने छात्रा की हत्या कर दी। हैवानियत पर उतरे टीचर ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से छात्रा के शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है।



गेस्ट टीचर था। आरोप है कि शिवेंद्र ने नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए, कुछ समय बाद नाबालिग प्रेगनेंट हो गई। जब उसने आरोपी टीचर से शादी की बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर लड़की उसपर दबाव बनाने लगी। छात्रा के दबाव से आरोपी टीचर परेशान हो गया। टीचर शिवेंद्र ने छात्रा को जान से मारने की प्लानिंग बनाई और 13 नवंबर को टीचर ने छात्रा को पड़ोस के एक खेत पर बुलाया। टीचर बायोटेक से बीएससी का छात्र रहा है। ऐसे में उसे पता है कि किस फल को खिलाने से छात्रा के गर्भ से निपटारा मिल जाएगा। टीचर ने छात्रा को जहरीला फल खिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने लड़की के शव को कुएं में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया।

छह दिन बाद खुलासा
इस मामले में छात्रा के परिजन ने जैतपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार दिन बाद छात्रा का शव कुएं से मिला। इस मामले की पड़ताल के लिए पुलिस अधीक्षक ने दो डीएसपी, छह टीआई के साथ एसआईटी टीम गठित की गई। पुलिस ने छह दिन बाद ही मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया।

दक्षिण मुंबई की पुरानी म्हाडा इमारतों का होगा पुनर्विकास

388 इमारतों के 30-40 हजार परिवारों को मिलेगी राहत ...!



मुंबई : सूबे की शिंदे-फडणवीस सरकार ने दक्षिण मुंबई की 30 साल पुरानी म्हाडा इमारतों के पुनर्विकास का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सेस इमारतों की तर्ज पर एफएसआई का लाभ देकर इनका पुनर्विकास किया जाएगा। इस निर्णय का लाभ 388 इमारतों में रहने वाले 30 से 40 हजार परिवारों को मिलेगा। इस बारे में अगले सप्ताह अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

स'द्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभाग के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सांसद राहुल शेवाले, भाजपा जिलाध्यक्ष मिलिंद तुलस्कर एवं म्हाडा पुनर्निर्चित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक इन इमारतों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया। विकास नियंत्रण नियमावली की धारा 33 (24) में संशोधन कर 33 (7) के सभी लाभों को लागू कर इमारतों का पुनर्विकास करने को लेकर सरकार सकारात्मक है। इस संबंध में अगले सप्ताह अधिसूचना जारी हो सकती है। सरकार के इस फैसले से जर्जर हो चुकी म्हाडा इमारतों में रहने वाले हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। म्हाडा की तरफ से इमारतों के पुनर्विकास का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही फैसला होने की संभावना है।

म्हाडा ने मुंबई में 14,000 से अधिक पुरानी और जर्जर इमारतों का पुनर्निर्माण किया है। इस इमारतों के किराएदारों के घरों का क्षेत्रफल 160 से 225 वर्ग फुट है। पुरानी इमारतों के रख-रखाव का खर्च बढ़ गया है, इसलिए इन इमारतों के पुनर्विकास की लगातार मांग जा रही थी। विकासक भी इन इमारतों के पुनर्विकास के लिए आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पुनर्विकास में पर्याप्त एफएसआई उपलब्ध नहीं हो रही थी। इन इमारतों का निर्माण कार्य 70 से 80 के दशक में किया गया था। इमारतों में कई परिवार रहते हैं। इनमें से कई की हालत जर्जर है। सबसे बड़ी समस्या कॉमन टॉयलेट की है। कई इमारतें पांच मंजिला हैं, लेकिन उनमें लिफ्ट नहीं है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार के फैसले से इन लोगों की समस्याओं का स्थाई रूप से समाधान हो सकेगा।

एसआरए की किशोरी पेडणेकर को नोटिस...!

एक सप्ताह में घर खाली करने का निर्देश



मुंबई : पूर्व महापौर और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की उपनेता किशोरी पेडणेकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है एसआरए ने किशोरी पेडणेकर को एक सप्ताह के भीतर वली गोमाता जनता हाउसिंग सोसायटी के चारो फ्लैट खाली करने का नोटिस भेजा है। चारों फ्लैट पर किशोरी पेडणेकर का कब्जा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। इसके पहले किशोरी पेडणेकर की दादर पुलिस स्टेशन में घंटों पूछताछ का भी सामना करना पड़ा था।

लोअर परेल स्थित गणपतराव कदम मार्ग स्वास्तिक मिल कंपाउंड स्थित गोमाता एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि. में बिल्डिंग नंबर 2 के फ्लैट क्रमांक 601 के नाम नोटिस भेजा गया है। एसआरए ने यह फ्लैट गंगाराम विरव्या के नाम आवंटित किया था। 10 वर्ष के पूर्व ही इस फ्लैट की हुई खरीद फरोख्त एसआरए शर्तों को भंग करने वाला था किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि महापौर किशोरी पेडणेकर ने अवैध रूप से इन फ्लैटों को हासिल किया है। इसके पहले कोरोना जर्बो कोविड सेंटर निर्माण में सोमैया ने आरोप लगाया था कि महापौर के बेटे की कंपनी किश कारपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया था। जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं था। हालांकि उस दौरान महाविकास आघाड़ी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरे मामले को ठंडे बास्ते में डाल दिया गया था। राज्य में अब सरकार बदलने के बाद किशोरी पेडणेकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एसआरए ने वली गोमाता जनता हाउसिंग सोसायटी में चार फ्लैट को खाली करने का नोटिस दिया है। किरीट सोमैया ने बताया कि पूर्व महापौर परिवार को झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ने सेक्शन 34 ए के अंतर्गत घर खाली कराने का नोटिस दिया है। यदि एक सप्ताह में घर खाली नहीं करती हैं तो एसआरए घरों को सील कर सकता है।



खसरे के प्रकोप से जूझ रहा मुंबई...!

टाकाकरण की कमी, खराब जीवन स्तर को ठहराया जा रहा जिम्मेदार

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही हो, लेकिन यह महानगर बच्चों में खसरे के भीषण प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि शहर में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है और 184 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। यह जानकारी नगर निकाय के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जीवन स्तर की दयनीय स्थिति, बड़ा परिवार, उचित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वच्छता सुविधाओं और पोषण की कमी, खराब प्रतिरक्षा, टीके की खुराक न देना और टीकाकरण के प्रति अनिच्छा शहर में इस बीमारी के पांव पसारने के कुछ प्रमुख कारण हैं।

नगर निकाय के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में इस साल खसरे के

मामलों में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जबकि 2020 में 25 और पिछले साल नौ मामले दर्ज किए गए थे। सरकार ने 2023 के अंत तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि महानगर में बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इससे पहले, मुंबई में 2019 में खसरे के कारण तीन मौतों की सूचना दी थी। वर्ष 2020 में नागपुर, चंद्रपुर और अकोला में एक-एक मौत दर्ज की गई थी। ठाणे और मुंबई में भी 2021 में एक-एक मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य निगरानी अधिकारी प्रदीप आवटे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि यदि एक सप्ताह में संक्रमण के पांच संदिग्ध मामले सामने आते हैं, जिनमें से दो से अधिक की प्रयोगशाला परीक्षण में पुष्टि हुई हो, तो इसे प्रकोप कहा जाता है।

राज्य बुलेटिन के अनुसार,



स्वास्थ्य विभाग खसरा के लिए घर-घर निगरानी कर रहा है और अभियान के रूप में विशेष टीकाकरण सत्रों की व्यवस्था की जा रही है। बुलेटिन के अनुसार, इस साल महाराष्ट्र में 17 नवंबर तक खसरे के 503 मामले दर्ज किये गये, जबकि 2019 में 153, 2020 में 193 और पिछले साल 92 मामले सामने आए थे। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण खसरे का नियमित टीकाकरण

कार्यक्रम प्रभावित हुआ है और परिणामस्वरूप खसरे के खिलाफ टीकाकरण भी बाधित हुआ। इसलिए बड़ी संख्या में बच्चे या तो पहली या दूसरी खुराक लेने से चूक गए। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमारे ने कहा, "अब हमने खसरे के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए तीन-सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है।"

अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही शून्य से दो वर्ष आयु वर्ग के 10,000 बच्चों को टीका लगाया है

और एक सप्ताह के भीतर इस आयु वर्ग के शेष 10,000 बच्चों तथा पांच वर्ष तक की आयु के 40,000 उन बच्चों का टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जो किसी कारण से टीके की खुराक से वंचित रह गये थे। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि इस साल सितंबर के आखिरी हफ्ते से मामले अचानक बढ़ने लगे और अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। सिविक द्वारा संचालित कस्तूरबा अस्पताल ने सितंबर में प्रकोप के बाद एक विशेष आइसोलेशन वार्ड जोड़ा। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि शहर के कुल 24 निगम क्षेत्रों में से आठ वार्ड के 17 इलाकों में बीमारी फैल गई है, जबकि कुछ मरीज कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं।

उन्होंने कहा कि संक्रमण का अधिकतम प्रसार एम-ईस्ट वार्ड में है, जिसमें गोवंडी और देवनार जैसे

क्षेत्र शामिल हैं, इसके बाद एल-वार्ड का स्थान आता है जिसमें कुर्ला और चूनाभट्टी क्षेत्र शामिल हैं। बीएमसी ने अब तक खसरे के 2,900 संदिग्ध मामलों का पता लगाया है, जिनमें बुखार और चकते जैसे सामान्य लक्षण वाले मरीज हैं। एक निगम अधिकारी ने कहा, "सभी मौतें मुस्लिम समुदाय से हुई हैं और जिन क्षेत्रों में वे रह रहे थे, उनमें भी (मुस्लिम) समुदाय का वर्चस्व है।" स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में कई फर्जी डॉक्टर भी हैं जो रोगियों को सही उपचार नहीं देते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दों को बिगड़ते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा डीपिंग ग्राउंड एम-ईस्ट वार्ड में स्थित है जहां ज्यादातर लोग गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अनुसार, वे अनौपचारिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और रहने की स्थिति अच्छी नहीं है।

राज कुंद्रा ने ओटीटी के लिए बनाई अश्लील फिल्में, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कहा...

मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति व बिजनेसमैन राज कुंद्रा और अन्य पर कुछ डीलक्स होटलों में पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने का आरोप लगाया गया है, जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा धन संबंधी लाभ के लिए वितरित किया गया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह एक अदालत के समक्ष दायर साइबर पुलिस चार्जशीट के अनुसार, कुंद्रा ने मॉडल शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे, एक फिल्म निर्माता मीता झुनझुनवाला और एक कैमरामैन राजू दुबे के साथ पांच सितारा होटलों में पोर्न वीडियो शूट किया था। इससे पहले 2021 में, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अप्रैल में अपनी अलग चार्जशीट दाखिल की थी, इसके बाद सितंबर में मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जो फरवरी (2021) में मध आइलैंड बंगले पर छापे के बाद सामने आया था। साइबर पुलिस, जिसने 2019 में मामला दर्ज किया था, ने दावा किया है कि आर्म्सप्राइम मीडिया लिमिटेड के निदेशक राज कुंद्रा कुछ वेबसाइटों पर अश्लील वीडियो बनाने और वितरित करने में शामिल थे। 450 पन्नों की



चार्जशीट में 'बनाना प्राइम ओटीटी' के सुवाजीत चौधरी और कुंद्रा के एक स्टाफ सदस्य उमेश कामथ समेत अन्य का नाम पोर्न कंटेंट बनाने वाली एक वेब सीरीज 'प्रेम पगलानी' का निर्माण करने और ओटीटी पर अपलोड करने के लिए शामिल किया गया है। पांडे पर अपना खुद का मोबाइल ऐप 'द पूनम पांडे' डेवलप करने, कुंद्रा की कंपनी की मदद से वीडियो शूट करने, अपलोड करने और सक्रिलेंट करने का भी आरोप है। साइबर पुलिस के अनुसार, दुबे ने चोपड़ा के वीडियो भी शूट किए थे, जबकि झुनझुनवाला पर उनके (चोपड़ा) लिए स्क्रिप्ट लिखने और निर्देशित करने में सहायता करने और उकसाने का आरोप है। साइबर पुलिस ने दावा किया है कि कुंद्रा की कंपनी ने अपराध में सहायता की और बढ़ावा दिया। इसने अन्य सभी

सह-अभियुक्तों से वित्तीय लाभ प्राप्त किया, हालांकि वे जानते थे कि ऐसी चीजें अवैध हैं, यहां तक कि वे कुछ अन्य लापता मॉडलों की तलाश में हैं जिन्होंने अश्लील वीडियो या वेब सीरीज में काम किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा इस हाई-प्रोफाइल मामले का खुलासा होने के बाद, जिसमें कई अभियुक्तों को पकड़ा गया था, कुंद्रा को सितंबर 2021 में जमानत मिलने से पहले दो महीने की हिरासत में भेज दिया गया था। अन्य आरोपियों में कुंद्रा की फर्म वियान एंटरप्राइजेज के आईटी प्रमुख रयान थोरपे, सिंगापुर में रहने वाले यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव और लंदन में रहने वाले कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी शामिल हैं, जो केनरीन और हॉटशॉट कंपनियां चला रहे हैं। मुंबई पुलिस, जिसने कुंद्रा पर लगभग 100 पोर्न फिल्में बनाने का आरोप लगाया था, ने ठाकुर के 6.50 करोड़ रुपये के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया, और सितंबर 2021 में अपनी पूरक चार्जशीट के अनुसार, मामले में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए।

एमपी में गरमाई राजनीति पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, युवा उद्यमियों के लिए उठाई यह मांग...



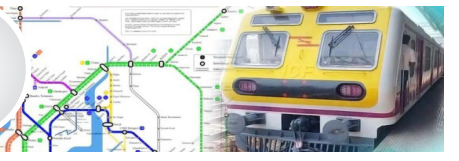
मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में कमलनाथ ने युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना और कृषक उद्यमी योजना के हितग्राहियों का मुद्दा उठाया है। नाथ ने कहा कि युवाओं ने शासन की योजनाओं के जरिए बैंकों से लोन लेकर रोजगार तो शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड की राशि नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ ने कहा कि इससे बैंक ऋण लेकर खुद का रोजगार स्थापित करने की कवायद में जुटे उद्यमियों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभावित व प्रेरित करने के लिए ब्याज अनुदान, अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी फंड दिया जाता है, इसी आस में लोन का जोखिम भी उद्यमियों ने उठा लिया लेकिन

पिछले दो साल से ब्याज अनुदान की राशि और तीन साल से क्रेडिट गारंटी फंड की राशि जारी नहीं की गई है, जिससे स्व रोजगारियों को व्यापार, व्यवसाय बंद करने की नौबत आ गई है या फिर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कोरोनाकाल में व्यापार और उद्यम को अत्यधिक नुकसान हुआ है। इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार को इन्हें संबल और राहत प्रदान करना चाहिए। सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं का समय सीमा में पालन नहीं करते हुए देय राशियां जारी नहीं कर रही है। बेरोजगारी के इस दौर में युवा उद्यमियों व स्व रोजगारियों के प्रति यह स्थिति चिंताजनक और स्वरोजगार के अनुकूल नहीं है। उन्होंने सहानुभूति पूर्वक इस संबंध में निर्णय लेकर प्रतिबद्धताएं पूरी करने का आग्रह किया है।

सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन क्यों मिली : पटोले



बुलढाणा । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को कहा कि जो लोग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की वी. डी. सावरकर पर टिप्पणी के लिए आलोचना कर रहे हैं उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि हिंदुत्व के विचारक को ब्रिटिश शासकों से पेंशन के रूप में 60 रुपये क्यों मिल रही थी। श्री पटोले ने कहा, "जिसने भी श्री सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणियों की आलोचना की, उन्हें पहले जवाब देना चाहिए कि सावरकर को अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन क्यों मिल रही थी।" उन्होंने कहा कि 'भारत जोड़ो यात्रा' को महाराष्ट्र में लोगों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। श्री गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई 'भारत जोड़ो यात्रा' से लोगों में साहस पैदा हुआ है और उन्हें भाजपा द्वारा पैदा किए गए भय, नफरत और आतंकवाद का जवाब देने की ताकत मिली है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस 19 नवंबर



पत्नी से झगड़े के बाद पति ने 6 साल के बेटे की गला रेतकर की हत्या!

मुंबई : मुंबई के मलाड इलाके से हैरान देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक बाप ने अपनी 6 साल के बच्चे हत्या कर दी है. इस संदर्भ में मालवनी पुलिस ने आरोपी बाप के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार



कर लिया है. मालवानी पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम नंदन अधिकारी जिसने अपनी पत्नी सुनीता के साथ पहले जमकर लड़ाई की और फिर पत्नी को परेशान करने के लिए उसने अपने बेटे लक्ष्य की कथित तौर पर हत्या कर दी.

जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था शव...
यह घटना शनिवार की सुबह

पुलिस ने किया गिरफ्तार

की है जब सुनीता अपनी 13 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने गई और जब वो वापस घर लौटी तो उसने देखा कि लक्ष्य का शव घर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा है, जिसके

बाप को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी और उसके पत्नी के बीच अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे और अब पत्नी को परेशान करने के लिए बेटे की हत्या कर दी.

बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा

बीते दिनों महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच काफी समय से किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था जिसके बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बेटे ने पिता को जान से मार डाला. मृतक की उम्र 60 साल की थी. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी बाप ने कबूल किया जुर्म...
एक अधिकारी ने बताया की हत्या करने के बाद पुलिस ने आरोपी

राज्यपाल के बयान पर भड़के शिवसेना (उद्धव) नेता संजय राउत महाराष्ट्र का हुआ अपमान, BJP से की ये मांग...!

मुंबई : छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को राज्य और मराठा शासक का 'अपमान' बताते हुए शिवसेना (उद्धव) नेता संजय राउत ने भाजपा नेताओं से उनके खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज को 'पुराने युग की बात' कह कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि पार्टी वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध कर रही है, और उन्हें अब राजभवन के खिलाफ विरोध करना चाहिए. संजय राउत ने कहा "उनका



बयान महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज का अपमान है. वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है. वे जूते मार रहे हैं. अब जूते राजभवन में जाने चाहिए जहां से शिवाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है." उन्होंने कहा "तभी तुम महाराष्ट्र के बेटे हो, वरना नहीं. इससे पहले शनिवार को औरंगाबाद में डॉ. बाबासाहेब

अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज अगर आपसे कोई पूछे की आपके पसंदीदा लीडर कौन हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे. शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग में डॉ. अंबेडकर से नितिन गडकरी तक यहीं मिल जाएंगे. शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के एक प्रवक्ता ने राज्यपाल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि वह महान नेताओं का अनादर करने के लिए जाने जाते हैं. उद्धव सेना के एक प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक बयान में कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं. वह हमेशा हम सभी के आदर्श रहेंगे."

कोरोना के बाद जमीन खरीदने वालों की संख्या तीन गुना बढ़ी मुंबई- दिल्ली सहित इन आठ जगहों पर बिकी सबसे ज्यादा लैंड



मुंबई : रियल एस्टेट डेवलपर मांग में तेजी आने के साथ ही अपने कारोबार में आक्रामक तरीके से विस्तार करना चाहते हैं. यही वजह है कि जमीन के सौदे बहुत तेजी से बढ़े हैं. इस साल जनवरी से सितंबर के बीच आठ प्रमुख शहरों में जमीन सौदे तीन गुना से अधिक होकर 68 हो गए हैं.

संपत्ति परामर्शदाता एनारॉक ने जानकारी दी. एनारॉक भूमि सौदों की जानकारी एकत्रित

करती है जिसमें डेवलपर की सीधी खरीद के साथ-साथ संयुक्त विकास समझौते भी शामिल होते हैं. एनारॉक ने बताया कि 2022 के पहले नौ महीनों में देश के शीर्ष आठ शहरों में कम से कम 68 भूमि सौदे हुए जिनका क्षेत्रफल 1,656 एकड़ है. पिछले साल समान अवधि में 20 सौदे हुए थे जिनका क्षेत्रफल 925 एकड़ था.

एनारॉक ने क्या कहा ?
एनारॉक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद भूमि सौदे बढ़ गए हैं. साल 2020 और 2021 की तुलना में आवासीय मांग बढ़ने के बाद सभी प्रमुख कंपनियों मसलन मेक्रोटैक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स भूमि सौदे कर रही हैं.

कांग्रेस ने शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की

बुलढाणा : कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को उनकी उन टिप्पणियों को लेकर वापस बुलाने की रविवार को मांग की, जिसमें उन्होंने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को "पुराने जमाने" के आदर्श के रूप में बताया था। पटोले ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से माफी की मांग करते हुए दावा किया कि उसके नेता सुधांशु त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। पटोले ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस 'वैचारिक रूप से स्वच्छ महाराष्ट्र' के लिए काम करेगी और वह समाज सुधारकों महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्यपाल कोश्यारी ने शनिवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में केंद्रीय



मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार को डी.लिट की उपाधि से नवाजते हुए महाराष्ट्र में 'आदर्श लोगों' की बात करते हुए बी आर अंबेडकर और गडकरी का जिक्र किया था तथा कहा था कि छत्रपति शिवाजी "पुराने जमाने" के आदर्श थे। पटोले ने दावा किया कि कोश्यारी ने महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी

की थी। उन्होंने शिवाजी महाराज पर टिप्पणियों के लिए राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी यह कहकर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी कि उन्होंने (शिवाजी महाराज) मुगल बादशाह औरंगजेब से पांच बार माफी मांगी। पटोले ने कहा, "इसे सहन नहीं किया जाएगा। भाजपा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और राज्यपाल

को वापस बुलाना होगा।" स्वतंत्रता सेनानी वी. डी. सावरकर पर टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना को लेकर पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने अंग्रेजों से निपटने में प्रतिष्ठित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और सावरकर की विचारधाराओं के बीच तुलना की थी। उन्होंने कहा, "यह एक वैचारिक तुलना है। राहुल गांधी विवाद पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन भाजपा ध्यान हटाना चाहती है। राहुल गांधी ने सावरकर (जब वह जेल में थे) की दया याचिका के दस्तावेजी सबूत भी दिखाए थे।" कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा, "जिस दिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद कर देंगे, हम उनके नेताओं के बारे में सच बताना बंद कर देंगे।"